सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक 280 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शुक्रवार 20 नवम्बर, 2026
मूल्य ₹ 3/-





कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी।

-जैक मा

भारतीय बल्लेबाजों का दूसरे दिन... 7 | यूपी में चुनाव से पहले गठबंधनों... 3 | बिना सबूत के आरोप लगा रहे... 2

यूपी बना कथाओं का प्रदेश

सियासत का नया प्रयोग

बाबाओं के भरोसे बीजेपी का चुनावी चक्रव्यूह

» मोदी-योगी के विकास का रिपोर्ट कार्ड कमजोर है या फिर हिंदुत्व का हथियार फिर धारदार किया जा रहा है?

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी आया नहीं है लेकिन चुनावी पटकथा के किरदार मंच पर उतरने लगे हैं। कहीं रामकथा है कहीं हनुमंत कथा कहीं भागवत का आयोजन तो कहीं शिवमहापुराण का दरबार। कथावाचकों की मांग बढ़ रही है और नेताओं के दरबार सज रहे हैं। धार्मिक आयोजनों में सियासत के दिग्गजों की आमद बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि अचानक उत्तर प्रदेश में कथाओं की इतनी बहार क्यों आ गयी है।

क्या प्रदेश में धर्म के प्रति आस्था का नया ज्वार आया है या फिर 2027 की चुनावी वैतरणी पार करने के लिए सियासत ने कथा और कथावाचकों को अपना नया सारथी बना लिया है। केंद्र में हैं बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। प्रतापगढ़ में आयोजित उनकी कथा सुनने के लिए नेताओं का जमावड़ा ऐसा लगा कि कथा के साथ-साथ सियासी ताकत का प्रदर्शन भी चर्चा में आ गया। कुंडा में राजा भैया की मेजबानी मंच पर बाबा बागेश्वर, आसपास भाजपा के दिग्गज, बृजभूषण शरण सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, निशिकांत दुबे और दूसरे राजनीतिक चेहरे। अब गोंडा में भाजपा विधायक बावन सिंह का आयोजन, झांसी में भाजपा विधायक रवि शर्मा की मेजबानी और फिर लखनऊ में सरोजनीनगर के भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के यजमानत्व में पांच दिवसीय हनुमंत कथा का कार्यक्रम। यह महज संयोगों की श्रृंखला है या चुनाव से पहले धार्मिक जनसंपर्क का एक नया अध्याय? इस पूरी तस्वीर के बीच एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। केंद्र में भी भाजपा की सत्ता है। डबल इंजन सरकार, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश, रोजगार, कानून-व्यवस्था और विकास के दावे लगातार गिनाए जाते हैं। अगर यह विकास जनता के मन में उतर चुका है। अगर सरकार अपने कामकाज को लेकर आश्वस्त है तो फिर चुनावी मैदान में बाबाओं और धार्मिक आयोजनों की इतनी बड़ी भूमिका क्यों दिखाई दे रही है। सवाल बड़ा और पेचीदा है कि क्या विकास का रिपोर्ट कार्ड अकेले चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। उधर आजम खां जेल से बाहर आ चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी की सियासी सक्रियता और बयानबाजी भी चर्चा में है। एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति का उभार दूसरी तरफ मुस्लिम राजनीति की गोलबंदी के प्रयास। ऐसे में आशंका है कि चुनावी बहस रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों और नौजवानों के सवालों से निकलकर फिर मंदिर-मस्जिद और हिंदू-मुस्लिम की धुरी पर पहुंच जाए। आजम खां ने जेल से बाहर आने के बाद खुद कहा है कि भविष्य के चुनाव केवल धर्म और जाति के आधार पर नहीं लड़े जाते।



“सवाल बड़ा और पेचीदा है कि क्या विकास का रिपोर्ट कार्ड अकेले चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है।”



उत्तर प्रदेश 2027

मथुरा का मुद्दा फिर गर्म भ्रष्टाचार पर खामोशी क्यों?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मथुरा का मुद्दा नया नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद मथुरा और काशी से जुड़े धार्मिक प्रश्न भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने रहे हैं। लेकिन यहां एक सवाल भाजपा से बनता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है ऐसे में सरकार इन उपलब्धियों को अपनी राजनीतिक सफलता के तौर पर प्रस्तुत क्यों नहीं करती। मथुरा के मुद्दे को लगातार राजनीतिक बहस में गर्म रखने की जरूरत क्यों महसूस होती है।

विकास का इतना भरोसा है तो बाबाओं की जरूरत क्यों?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए बहुत कुछ है। फिर आखिर चुनावी माहौल में धार्मिक आयोजनों की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। क्या रोजगार के मोर्चे पर सवाल नहीं हैं? क्या महंगाई आम आदमी की चिंता नहीं है? क्या युवाओं को सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का हिसाब नहीं चाहिए? क्या किसानों की आय, गन्ने का भुगतान, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहस नहीं होनी चाहिए? और भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार का मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि सत्ता की जवाबदेही का मुद्दा है। जनता यह जानना चाहती है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता कितनी है स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लगा और सरकारी तंत्र आम आदमी के प्रति कितना जवाबदेह हुआ। लेकिन यदि चुनावी विमर्श में इन सवालों की जगह केवल धार्मिक पहचान और भावनात्मक मुद्दे ले लेते हैं तो लोकतंत्र के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं होगी।

सियासत के तौर-तरीके भी बदलते दिखाई दे रहे

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ सियासत के तौर-तरीके भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक दलों के मंचों के साथ अब धार्मिक मंचों की अहमियत बढ़ रही है। बड़े-बड़े कथावाचकों की मांग है, आयोजकों में नेताओं के नाम हैं और कार्यक्रमों में राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी सुर्खियां बटोर रही है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की है। कुंडा से लेकर गोंडा, झांसी और लखनऊ तक उनकी कथाओं की श्रृंखला बन रही है। इसके अलावा राजन जी महाराज, प्रदीप मिश्रा और दूसरे कथावाचकों के कार्यक्रम भी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित हो रहे हैं। जरा इस सियासी कैलेंडर को देखते हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया की मेजबानी में बाबा बागेश्वर की रामकथा का आयोजन चल रहा है आज अंतिम दिन है। गोंडा में भाजपा विधायक बावन सिंह के आयोजन में 4 से 6 दिसंबर तक कथा होनी है। झांसी में भाजपा विधायक रवि शर्मा से जुड़ा 11 से 13 दिसंबर का कार्यक्रम फाइनल हो चुका है। लखनऊ के सरोजनीनगर में विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के यजमानत्व में 21 से 25 दिसंबर तक हनुमंत कथा होगी। आगरा में भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम प्रस्तावित है। यह सूची अपने आप में बताती है कि धार्मिक आयोजनों का दायरा किस तरह बढ़ रहा है।

बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं सीएम : अखिलेश

» सपा प्रमुख ने की गोरखपुर हादसे की जांच की मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन विधानसभा चुनाव की तारीख का एलान होगा, उसी दिन भाजपा की हार की इबारत लिख जाएगी। भाजपा जनता का विश्वास खो चुकी है। वह बृहस्पतिवार को सपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का आखिरी चुनाव और संविधान व आरक्षण बचाने का अंतिम अवसर है। भाजपा सरकार में बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। भाजपा का काम अनर्गल आरोप लगाना और बिना सिर-पैर की बातें करना रह गया है। आरोप लगाया कि भाजपा पीडीए के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। ऐसे हालात में कार्यकर्ताओं को धैर्य से काम लेना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भाषा में संयम रखने और व्यवहार व आचरण से उदाहरण पेश करने की नसीहत दी। गोरखपुर हादसे में मासूम की मौत पर शोक जताते हुए अखिलेश ने कहा कि इस घटना से सभी आहत हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई और कहा कि परिवार से मिलकर हरसंभव सहायता करने के लिए कह चुके हैं। उन्होंने हादसे पर राजनीति करने वालों को लखनऊ अग्निकांड में मृत युवक की दुखी मां के साथ किए गए दुर्व्यवहार और धमकी की याद दिलाई। सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो पोस्ट कर उन्होंने कहा कि यह वीडियो गवाह है कि गोरखपुर में युवक की मौत पर मुख्यमंत्री बिना सबूत दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, जो निंदनीय है। उन्होंने हादसे की सर्वोच्च स्तरीय जांच कराकर सच सामने लाने की मांग की।



समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान जेसीबी की चपेट में आने से हुई 14 वर्षीय छात्र आर्यवर्धन की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सपा के गुंडों ने एक नाबालिग बच्चे को कुचलकर उसकी निर्मम हत्या की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के साथ इस तरह की क्रूरता अक्षम्य है।परिवार से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतक बच्चा चौरी-चौरा की ऐतिहासिक घटना से जुड़े एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के परिवार का सदस्य था। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के मामले में जिन 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनमें इस परिवार के बुजुर्ग भी शामिल थे। मुख्यमंत्री के अनुसार, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इन लोगों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलवाने में सफलता मिली थी।

पीड़ित परिवार से मिले योगी

कांग्रेस से सीट बंटवारे के लिए सपा ने बनाई कमेटी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन और सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए एक कमेटी का गठन किया है। सपा ने सांसद रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय गठबंधन कमेटी बनाई है। यह कमेटी कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करेगी। इस कमेटी में सपा के पांच नेताओं के साथ दो डेटा एक्सपर्ट भी शामिल होंगे।

रामगोपाल यादव करेंगे अध्यक्षता

इस तरह कांग्रेस से बातचीत के लिए सपा की कुल सात सदस्यीय टीम तैयार की गई है। सपा की ओर से पांच नेता कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। दोनों दलों के बीच 23 और 24 नवंबर को बातचीत होनी है। सपा ने अपनी इस कमेटी में दो डेटा एक्सपर्ट भी शामिल किए हैं जो हर सीट के आंकलन की जानकारी पार्टी नेताओं के साथ शेयर करेंगे और इसके आधार पर ही फाइनल मुहर लग सकती है। बता दें कि यूपी चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 181 सीटों की मांग की है। हैरानी वाली बात ये हैं कि कांग्रेस ने जो 181 सीटें सपा से मांगी हैं, उनमें 169 सीटें ऐसी हैं जिसपर कांग्रेस 2022 में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। कांग्रेस की 181 सीटों की लिस्ट में 135 सीट सामान्य, 45 अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित सीटें और एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीट शामिल हैं।

कांग्रेस ने जब सपा को 182 सीटों की लिस्ट भेजी तो उस लिस्ट के सवाल पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि अभी सीट-शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, एक-दूसरे का सम्मान करते हुए हम सीटों का तालमेल बिठा लेंगे। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे।

दाढ़ी रख लेने से हर कोई मौलाना नहीं बन जाता : आजम

» जेल से बाहर आते ही ओवैसी पर आजम का हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रामपुर। जेल से निकलने के बाद आजम खान का बड़ा बयान सामने आ गया। आजम खान ने कहा कि अब चुनाव नहीं इंकलाब होगा। आजम खान ने ये भी ऐलान कर दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को वो लड़ेंगे। अब लोग धर्म-जाति के नाम पर नहीं लड़ेंगे। आजम खान ने कहा कि न्याय तो न्याय है, लेकिन बदला किसी से नहीं लिया जाएगा। आजाम खान ने रिहाई के बाद बीजेपी पर भी निशाना साधा। आजम ने कहा कि बीजेपी बेइमानी से जीती है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आपने पार्लियामेंट के नतीजे नहीं देखें। विधानपरिषद के नतीजे नहीं देखें क्या थे। ये जो सीटें जीती हैं वो बेइमानी से जीती हैं।

आजम खान ने इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठाए हैं। आजम खान का आरोप है कि रामपुर में पहली बार वोट चोरी होने पर गठबंधन ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान लोगों को हथियार दिखाकर डराया-धमकाया गया और उन्हें वोट देने से रोका गया, जिससे वे अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सके। आजम के मुताबिक, यह सीधा-सीधा रामपुर का चुनाव लूटने जैसा था। आजम खान का कहना है कि अगर इंडिया ब्लॉक ने उसी समय इस मामले को गंभीरता से उठाया होता तो हरियाणा और महाराष्ट्र में भी ऐसी घटनाएं नहीं होतीं।आजम खान ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, वो मौलाना नहीं हैं, बैरिस्टर हैं। दाढ़ी रख लेने से हर आदमी मौलाना नहीं बन जाता और न ही साधु बन जाता है। अभी बहुत से मौके आएंगे इसपर बात करेंगे, हैदराबाद की बिरयानी हमारे यहां पसंद नहीं की जाती है।



आजम बोले- मुझे देश छोड़ने की अनुमति दे सरकार, या दे इच्छा मृत्यु

जेल से रिहाई के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां ने चुप्पी तोड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार, जांच एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं पर तीखे सवाल उठाए। कहा कि अगर उनसे इतनी ही नफरत है तो सरकार उन्हें पूरे परिवार समेत इच्छा मृत्यु दे दे या फिर देश छोड़ने की इजाजत दे। इन दोनों में से कोई एक फैसला तो किया जा सकता है। आजम खां ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में नफरत का एजेंडा चलाया जा रहा है और शिक्षा का मंदिर बनाने और मुसलमान होने की उन्हें सजा दी जा रही है। जौहर विश्वविद्यालय को लेकर उन्होंने कहा कि जब विश्वविद्यालय तोड़ने की बात सुनी तो सोचा था कि खंडहरों में बच्चों को पढ़ाएंगे। दुनिया को बताएंगे कि लोग रोमन साम्राज्य के खंडहर देखने जाते हैं, वैसे ही जौहर विश्वविद्यालय भी देखने आएं। इसे दुनिया के लिए मिसाल बना देंगे। उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत भवन वर्ष 2004, 2005 और 2006 में ही तैयार हो चुके थे। इसके बावजूद आयकर विभाग ने गलत दरों के आधार पर आकलन किया और दिल्ली का रेट लगा दिया। आजम खां ने कहा कि उनके पास इस घर के अलावा कोई दूसरा मकान नहीं है। 50 साल तक लखनऊ की राजनीति में रहने और चार बार मंत्री बनने के बावजूद उन्होंने दूसरा घर नहीं बनाया। ईडी, आयकर विभाग, विकास प्राधिकरण और सीबीआई जैसी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनके कारण बहुत से लोग परेशान हैं। संवैधानिक संस्थाओं को अपनी साख खुद बचानी चाहिए और सोचना चाहिए कि देश उनके बारे में क्या सोच रहा है। चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी वजह से दुनिया में देश की बदनामी हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बदले की राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि जिन्हें इंसाफ नहीं मिला है, उन्हें इंसाफ दिलाएंगे।

अयोध्या में कल आकाश आनंद भरेंगे हुंकार

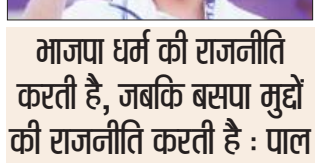
» जितेंद्र सिंह बबलू के टिकट का कर सकते हैं ऐलान

» बसपा ने राजनीतिक तैयारियां तेज की

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

अयोध्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कल 20 नवंबर को बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद अयोध्या में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा का आयोजन सोहावल क्षेत्र के पंडितपुर में बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किया जाएगा।

इस जनसभा के जरिए बसपा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी ताकत दिखाने और चुनावी हुंकार भरने की तैयारी में है। इस दौरान जितेंद्र बबलू को टिकट दिए जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद लगातार रैलियां और जनसभाएं कर चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। इस दौरान वे प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर रहे हैं। जनसभा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान विश्वनाथ पाल और पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा प्रदेश में सरकार बनाएगी। बीकापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को बसपा प्रत्याशी घोषित किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है।



भाजपा धर्म की राजनीति करती है, जबकि बसपा मुद्दों की राजनीति करती है : पाल

वहीं, भाजपा द्वारा अयोध्या के बाद मथुरा को मुद्दा बनाए जाने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, जबकि बसपा मुद्दों की राजनीति करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि जनता के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरेगी जनसभा के बाद अयोध्या की चारों विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने के भी संकेत मिले हैं।



बिहार में संविधान को फाड़कर कूड़े में फेंका : तेजस्वी

» राजद बोली- नौ महीने से फर्जी मंत्री को सरकार में बैठा रखा है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक व्यक्ति के एक साथ मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद के पद पर रहने को लेकर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने संविधान और नियमों की अनदेखी करते हुए नौ महीने से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना रखा है, जिसकी नियुक्ति और पद पर बने रहने को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं।

उन्होंने दावा किया कि लोकभवन ने भी एक व्यक्ति के तीन पदों पर रहने को लेकर आपत्ति जताई है। तेजस्वी ने कहा कि इस मामले को लेकर वह ऊपर तक जाएंगे। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बिहार सरकार पर संविधान की अवहेलना का आरोप लगाया।

उन्होंने लिखा, बिहार सरकार ने संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। नौ महीनों से एक फर्जी मंत्री को सरकार में बैठा रखा है और वह अवैध मंत्री हर प्रकार के अवैधानिक कार्यों में संलिप्त है। तेजस्वी ने दावा किया कि लोकभवन ने एक ही व्यक्ति के एक साथ तीन पदों पर रहने यानी मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद होने पर गंभीर आपत्ति जताई है।

उन्होंने कहा कि संविधान के प्रावधानों और नियमों के विपरीत संबंधित व्यक्ति की सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति की गई। तेजस्वी यादव ने सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति और उसके बाद छुट्टी पर जाने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रियाओं और नियमों की अनदेखी की गई। उनके मुताबिक, नियुक्ति के अगले ही दिन संबंधित व्यक्ति प्रोबेशन अवधि के दौरान लंबी और अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए।



यूपी में चुनाव से पहले गठबंधनों पर रार

सपा और कांग्रेस में नहीं बन रही बात

- बसपा अकेले लड़ने की तैयारी में जुटी
- भाजपा के सहयोगी भी पूरे तेवर में
- रावण की पार्टी व ओवैसी की पार्टी में बनी बात

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी में चुनाव आने में अभी समय है। पर सभी सियासी दलों में गठबंधन को लेकर उतार-चढ़ाव शुरू हो गया है। जहां आजाद पार्टी व एआईएमआईएम में गठबंधन हो गया है वहीं भाजपा के सहयोगी दल भी उस पर दबाव बनाने लगे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को शुरुआती तौर पर लगभग 24 सीटें देने का प्रस्ताव रख सकती है। इस प्रस्ताव का आधार 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रदर्शन बताया जा रहा है। खास तौर पर उन सीटों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों को 20 हजार से अधिक वोट मिले थे।

उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अभी चुनावी बिगुल पूरी तरह बजा भी नहीं है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के भीतर सीटों की लड़ाई ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। एक तरफ कांग्रेस 181 सीटों की मांग के साथ समाजवादी पार्टी के सामने बराबरी के साझेदार का दावा ठोक रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने महज 24 सीटों के शुरुआती प्रस्ताव के जरिए साफ संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति समाजवादी पार्टी की शर्तों पर ही आगे बढ़ेगी। देखा जाये तो कांग्रेस के लिए यह सिर्फ सीटों का मामला नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की लड़ाई है। वहीं अखिलेश यादव के लिए यह सवाल है कि जिस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में मजबूत क्षेत्रीय संगठन और बड़ा जनाधार है, वह अपने राजनीतिक हिस्से पर समझौता क्यों करे? बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को शुरुआती तौर पर लगभग 24 सीटें देने का प्रस्ताव रख सकती है। इस प्रस्ताव का आधार 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रदर्शन बताया जा रहा है। खास तौर पर उन सीटों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों को 20 हजार से अधिक वोट मिले थे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 181 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी है। यानी दोनों दलों के बीच शुरुआती अंतर ही 157 सीटों का है। यह अंतर बताता है कि बातचीत कितनी कठिन होने वाली है।



सीएम के गढ़ में अखिलेश का रोड शो

सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में रोड शो करने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे अखिलेश यादव एयरपोर्ट से पीडीए रथ में सवार होकर निकले। वो चौरीचौरा क्षेत्र के देवकही गांव तक रोड शो करें। इसके बाद देवकही में जनसभा को संबोधित किया और फिर अमर शहीद बाबू बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता जुटे एयरपोर्ट से चौरीचौरा तक जगह-जगह लोग उनका स्वागत किया। पीडीए रथ के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम चला। गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र स्थित सूबा बाजार हनुमान मंदिर के पास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत की तैयारी की गई है। पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उनके पहुंचने का इंतजार कर रहे थे।

कांग्रेस की 181 सीटों की मांग

दरअसल, कांग्रेस की 181 सीटों की मांग के पीछे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साफ दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में छह लोकसभा सीटें जीती थीं। अमेठी और रायबरेली जैसे क्षेत्रों में उसकी वापसी ने पार्टी के भीतर यह उम्मीद पैदा की कि विधानसभा चुनाव में भी उसे बड़ा राजनीतिक विस्तार मिल सकता है। कांग्रेस अब गठबंधन में केवल सहयोगी की भूमिका निभाने के बजाय अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक ताकत को फिर से स्थापित करना चाहती है। 181 सीटों की मांग इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन अखिलेश यादव के सामने भी अपनी अलग राजनीतिक मजबूरियां हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के खाते में महज दो सीटें आई थीं। ऐसे में सपा नेतृत्व कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक ताकत का आकलन पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर कर रहा है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर उन्होंने कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटें दे दीं, तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के अपने उम्मीदवारों, मौजूदा विधायकों और क्षेत्रीय समीकरणों पर पड़ेगा।

कांग्रेस के सामने भी पीछे हटने का विकल्प आसान नहीं

दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने भी पीछे हटने का विकल्प आसान नहीं है। यदि पार्टी 24 या उसके आसपास सीटों पर समझौता करती है, तो उसके प्रदेश संगठन में यह संदेश जा सकता है कि कांग्रेस फिर से समाजवादी पार्टी की छोटी सहयोगी बनकर रह गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ना उसके दीर्घकालिक विस्तार की रणनीति को कमजोर कर सकता है। हालांकि 24 सीटों का प्रस्ताव अंतिम समझौता नहीं, बल्कि शुरुआती मोलभाव की स्थिति है। राहुल गांधी ने भी सीटों के बंटवारे में उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता को महत्व देने की बात कही है। इसका अर्थ है कि कांग्रेस अपनी 181 सीटों की मांग पर कुछ नरमी दिखा सकती है, लेकिन सम्मानजनक हिस्सेदारी की शर्त से पीछे हटना उसके लिए आसान नहीं होगा।



24 सीटों के शुरुआती प्रस्ताव के जरिए अखिलेश यादव ने साफ संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति समाजवादी पार्टी की शर्तों पर ही आगे बढ़ेगी।

अखिलेश यादव 24 सीटों के शुरुआती दांव से अपनी मजबूत स्थिति दिखा रहे

बहरहाल, अखिलेश यादव 24 सीटों के शुरुआती दांव से अपनी मजबूत स्थिति दिखा रहे हैं, जबकि कांग्रेस 181 सीटों की मांग के जरिए अपनी राजनीतिक हैसियत स्थापित करना चाहती है। 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में यह सिर्फ सीटों का गणित नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीति के भीतर वर्चस्व की लड़ाई है। भाजपा के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने का दावा करने वाले दोनों दलों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सत्ता के खिलाफ लड़ाई शुरू होने से पहले वे एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक मुकाबले में न उलझ जाएं।

समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायकों वाली लगभग 22 सीटें पर भी कांग्रेस की नजर

सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कांग्रेस की 181 सीटों की सूची में समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायकों वाली लगभग 22 सीटें भी शामिल बताई गई हैं। इनमें अमेठी, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण सीटें भी हैं। यही वह बिंदु है जहां गठबंधन की दोस्ती और राजनीतिक हित आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने सांसदों के प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्रों पर दावा कर रही है, जबकि सपा अपने मौजूदा विधायकों और परंपरागत वोट बैंक वाली सीटों को छोड़ने के मूड में नहीं दिखती। देखा जाये तो अखिलेश यादव का 24 सीटों का शुरुआती प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कांग्रेस को एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देता है। संदेश यह है कि लोकसभा चुनाव की सफलता को विधानसभा चुनाव में सीटों की हिस्सेदारी का सीधा आधार नहीं बनाया जा सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा का चुनाव अलग सामाजिक समीकरणों, स्थानीय उम्मीदवारों और बूथ स्तर के संगठन पर लड़ा जाता है। सपा मानती है कि मुस्लिम-यादव आधार और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच उसकी राजनीतिक पकड़ उसे गठबंधन में स्वाभाविक रूप से बड़ी हिस्सेदारी का हकदार बनाती है।

जिद... सच की



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_SanjayS

आज फिर भारत को इंदिरा गांधी सी साहस की जरूरत

“ इंदिरा गांधी की साहस आज फिर देश को चाहिए। पं. जवाहरलाल नेहरू के घर 19 नवम्बर 1917 को जब प्रियदर्शिनी नामक कन्या ने जन्म लिया था तो किसे पता था कि यही कन्या आगे चलकर न केवल इस देश की बागडोर संभालेगी बल्कि अपनी दबंगता से पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगी।

वृहस्पतिवार को पूरे देश ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को याद किया। उनके जन्मदिन पर इस आयरन लेडी को सभी ने उनके जन्मदिन पर पुष्पाजंलि दी। पूर्व पीएम इंदिरा के कार्यकाल में भारत ने एक सशक्त देश के रूप में पूरी दुनिया में झंडा बुलंद किया। आज की पीढ़ी को भी उनके मागदर्शन में देश सेवा का संकल्प लेना चाहिए जो उन्होंने जीवित रहते मानदंड बनाए थे उसी से देश ने कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की थी। इंदिरा गांधी की साहस आज फिर देश को चाहिए। पं. जवाहरलाल नेहरू के घर 19 नवम्बर 1917 को जब प्रियदर्शिनी नामक कन्या ने जन्म लिया था तो किसे पता था कि यही कन्या आगे चलकर न केवल इस देश की बागडोर संभालेगी बल्कि अपनी दबंगता से पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगी। ऑक्सफोर्ड और स्विट्जरलैंड में उच्च शिक्षा प्राप्ति के पश्चात इंदिरा गांधी ने उच्च पद पर नौकरी करने या कोई अन्य कार्य करने के बजाय अपना जीवन देशसेवा में समर्पित करने का निश्चय किया।

देशभक्ति की भावना इंदिरा जी में बचपन से ही कूट-कूटकर भरी थी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आव्हान से प्रेरित होकर बचपन में ही इन्होंने अपने घर के बाहर अपने कीमती कपड़ों की होली जलाकर न केवल अपनी इसी भावना का परिचय दिया था बल्कि उसके बाद इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर इस आन्दोलन ने पूरे देश में जोर पकड़ा था। इंदिरा जी के स्कूली दिनों में एक दिन स्कूल में गांधी जी के आमरण अनशन को लेकर एक सभा का आयोजन था, जिसमें बच्चों को भी बोलने का अवसर दिया गया था। जब इंदिरा जी ने बोलना शुरू किया तो सभागार में सन्नाटा छा गया और सभी एकटक इंदिरा को निहारने लगे कि इतनी छोटी बालिका इतनी गूढ़ बातें कैसे कर रही है। उन्होंने कहा, ''आखिर स्वर्ण अपने ही दलित भाईयों को गिरा हुआ, छूत और निकृष्ट क्यों समझते हैं तथा उनके साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार क्यों करते हैं? अगर हमने अपनी ही सेवा करने वालों का इस तरह से निरन्तर तिरस्कार न किया होता तो आज अंग्रेजों को इस प्रकार लाभ उठाने का अवसर न मिल रहा होता और न ही बापू को इस तरह से आमरण अनशन कर अपने प्राण दांव पर लगाने पड़ते।'' इंदिरा जी की इन गूढ़ और तर्कसम्मत बातों के समक्ष सभी नतमस्तक थे और उनकी सराहना कर रहे थे। इंदिरा में बचपन से ही एक अच्छी राजनेता होने के तमाम गुण विद्यमान थे। 21 वर्ष की आयु में वह कांग्रेस में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में कूद पड़ी। उसके बाद उन्होंने आजादी के आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

युवाओं का भरोसा फिर से कायम करने का समय

गुरबचन जगत

जैसा कि जीन-जैक्स रूसो ने कहा है—'सामाजिक अनुबंध' वह आधार है जिस पर नागरिक साझी व्यवस्था बनाने एवं जनकल्याण के लिए, अपनी नैसर्गिक स्वतंत्रता को संप्रभु शासन अथवा कानून के अनुसार चलने वाली सरकार द्वारा शासित होने के लिए छोड़ना गवारा करते हैं अर्थात वोलोन्टे जेनरल (स्वैच्छिक सामान्य इच्छा)। और यह 'सामाजिक अनुबंध' आज दुनिया के अधिकांश हिस्सों में टूटा पड़ा है। युद्ध, दंगे, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हड़तालें इस घटनाक्रम का स्पष्ट प्रतिबिंब हैं। चरम आंदोलन और पार्टियों का उदय, चाहे वे चरम वामपंथी हों या दक्षिणपंथी, खतरनाक समय के अग्रदूत हैं। सरकार और नागरिक, दोनों को, इस टूटे अनुबंध पर पुन: विचार करना चाहिए। मैं इसे टूटा हुआ कहता हूं क्योंकि राज्य के सात प्राथमिक कर्तव्य-रक्षा एवं सुरक्षा; कानून एवं व्यवस्था; न्याय; अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा; सार्वजनिक वस्तुएं और बुनियादी ढांचा निर्माण; आर्थिक प्रबंधन; और सामाजिक कल्याण आज अधिकांश देशों में अव्यवस्था की स्थिति में हैं।

हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां दुनिया परस्पर युद्धरत है। मानव जाति का इतिहास मोटे तौर पर युद्ध का वर्णन ही है। इलाके, व्यापार और साम्राज्य-निर्माण को को लेकर युद्ध, आंतरिक अस्थिरता से ध्यान भटकाने और 'विदेशी हाथ' को दोष देने की इच्छा रखने वाले नेताओं द्वारा हमेशा उचित ठहराया जाता है। इन युद्धों में राष्ट्र एक-दूजे पर हमले करते रहते हैं और लाखों-करोड़ों निर्दोष लोग फंस जाते हैं। मतलब यह भी कि देश की संपत्ति और वित्त का बड़ा हिस्सा युद्धक प्रयासों में लगा दिया जाता है, नतीजन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक उत्थान पर जोर कहीं पीछे छूट जाता है, देश के भीतर असमानता एवं कलह बढ़ जाती है। आज जिस ओर भी देखें, हम देशों को युद्ध में उलझे पा रहे हैं या तो वे सीधे तौर पर शामिल हैं, सक्रिय या निष्क्रिय रूप से मदद दे रहे हैं या व्यापक विध्वंस पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन को नाटो और रूस को चीन एवं उत्तर कोरिया का समर्थन प्राप्त है।

रूसी और यूक्रेनी अर्थव्यवस्थाएं खस्ताहाल हैं, यूक्रेन को हथियारों और सामरिक समर्थन की एवज में अमेरिका को अपने विशाल प्राकृतिक संसाधन देने पड़ रहे हैं। रूस लगभग पूर्ण आर्थिक नाकेबंदी के तहत है, वह चीन पर अत्यधिक निर्भर है। रूसी-यूक्रेनी तेल, गैस और गेहूं की बाधित आपूर्ति के चलते बढ़ी मुद्रास्फीति के कारण दुनिया के बाकी हिस्सों को भी भारी नुकसान हो रहा है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और



अन्य यूरोपीय देशों ने अपने अन्य क्षेत्रों की एवज में सैन्य खर्च में भारी वृद्धि की। यूरोप अब घरेलू अशांति, कलह का नया मैदान है। फ्रांस, इटली, जर्मनी व सर्बिया में हाल में हिंसक आंदोलन हुए जिनमें सैकड़ों-हजारों प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से भिड़ते रहे। संपत्तियां लूटी गईं या नष्ट की गईं। फ्रांस में, आंदोलन छात्र प्रदर्शनों के साथ शुरू हुआ और समाज के अन्य वर्गों में फैल गया, जिसमें पैरेंट्स, शिक्षक और पेशेवर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। छात्र दोयम बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की कमी को लेकर आंदोलनरत थे। जैसे-जैसे यह अन्य वर्गों में फैला, पर्याप्त और सस्ते आवास की समस्या, जीवनयापन की बढ़ती लागत और तेल की कीमत जैसी मांगें जुड़ती गईं। इन देशों में अनियंत्रित आप्रवासन को अक्सर अव्यवस्था के लिए दोषी ठहराया जाता है। एक दशक से, अधिकांश यूरोप में बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति व जीवन स्तर में गिरावट सहित अर्थव्यवस्था गतिहीन पड़ी है। इसी तरह, अगर मध्य पूर्व को देखें, तो लगता है हर कोई हर किसी से लड़ रहा है, ईरान अमेरिकियों और इस्राइलियों के निशाने पर है। युद्ध ने पूरे क्षेत्र को चपेट में ले लिया और इसके नतीजे ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुन: प्रभावित किया, बढ़ती मुद्रास्फीति, बाधित आपूर्ति श्रृंखला व जीवनयापन की बढ़ी लागत ने अधिकांश परिवारों को हानि पहुंचाई। दक्षिण अमेरिका में, अमेरिका ने वेनेजुएला पर करीब कब्जा कर लिया। 'डोनरो डॉक्ट्रिन' (मोनरो डॉक्ट्रिन का डोनाल्ड ट्रंप संस्करण) को अपनी नीति का आधार बना अमेरिका सैन्य व आर्थिक रूप से महाद्वीप पर हावी होने की कोशिश में है। एशिया में, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हिंसक आंदोलन और उसके साथ सत्ता परिवर्तन देखा गया।

उन सभी में समान सूत्र यह कि सरकार और लोगों के बीच 'सामाजिक अनुबंध', अक्षरश और भावनात्मक रूप से, दोनों तरह, टूटा हुआ प्रतीत होता है। घर की बात करें तो, भारत की 1951 की जनगणना के अनुसार, शिक्षित लोग (कम से कम मैट्रिक पास) की संख्या पूरी आबादी (लगभग 36 करोड़) का करीब 1 फीसदी यानि 36 लाख थी; स्नातक बेरोजगारी उस 1 प्रतिशत की लगभग 5 फीसदी (लगभग 2 लाख) थी। इसकी तुलनाआज युवा स्नातकों में लगभग 40 प्रतिशत बेरोजगारी से करें।

बच्चों की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी

डॉ. अर्चना शर्मा



आज बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न घर की चारदीवारी से लेकर स्कूल, सड़क, सार्वजनिक स्थान और डिजिटल दुनिया तक फैला हुआ है। आज बाल सुरक्षा का अर्थ केवल बच्चों को शारीरिक शोषण से बचाना नहीं, बल्कि उन्हें भावनात्मक, सामाजिक और डिजिटल दुनिया में भी सुरक्षित वातावरण देना है। भारत में बच्चों की सुरक्षा के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। शारीरिक और यौन शोषण, बाल श्रम, बाल विवाह, मानव तस्करी, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग, असुरक्षित परिवहन तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बच्चों के अधिकारों और विकास को प्रभावित करती हैं। भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं। बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो, 2012 बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों को रोकने और उनसे जुड़े मामलों में कार्रवाई का कानूनी आधार प्रदान करता है।

किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण, अधिनियम, 2015 कानून से संघर्षरत बच्चों और देखरेख की जरूरत वाले बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास तथा पुन:समाजीकरण की व्यवस्था करता है। वहीं, मिशन वात्सल्य बच्चों की देखभाल और संरक्षण से जुड़ी सेवाओं को मजबूत करने का प्रयास है। इसके अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, 24 घंटे संकट में फंसे बच्चों तक सहायता पहुंचाने के लिए संचालित है और आपातकालीन सेवा 112 से एकीकृत है। सरकार ने 2025 में मिशन वात्सल्य पोर्टल को भी उन्नत किया, ताकि बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बेहतर हो सके। लेकिन कानून और योजनाएं तभी प्रभावी होती हैं, जब वे जमीन पर बच्चों तक पहुंचें। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 के आंकड़ों के अनुसार, देश में बच्चों के विरुद्ध अपराध के 1,62,449 मामले दर्ज हुए।

यह संख्या केवल कानूनी चुनौती नहीं, बल्कि सुरक्षा, जागरूकता और समय पर सहायता की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम के साथ-साथ उन परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है, जिनमें बच्चे स्वयं हिंसक व्यवहार की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। हाल के वर्षों में स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर कम उम्र के बच्चों के बीच मारपीट, धमकी, समूह में किसी बच्चे को निशाना बनाना और आक्रामक व्यवहार की खबरें चिंता पैदा करती हैं। हालांकि, ऐसी घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं कि 13 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों में हिंसा बढ़ रही है। इसके लिए आयु-विशिष्ट और तुलनात्मक राष्ट्रीय आंकड़ों की जरूरत है। फिर भी, किसी बच्चे का बार-बार हिंसक होना एक चेतावनी है, जिसे केवल अनुशासनहीनता कहकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसके पीछे उपेक्षा, घरेलू तनाव, बुलिंग, भावनात्मक कठिनाई, एकल परिवार, हिंसक सामग्री का संपर्क या साथियों का दबाव जैसे अनेक कारण हो सकते हैं। मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की भूमिका पर भी संतुलित दृष्टि आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, एकल परिवारों में माता-पिता बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। अक्सर बच्चे टीवी और मोबाइल पर अपना समय व्यतीत करते हैं।

परंतु ये दोनों ही गतिविधियां कई बार माता-पिता की निगरानी के बिना होती हैं। टीवी और डिजिटल मीडिया बच्चों को कुछ नया सीखने, रचनात्मकता और मनोरंजन के अवसर देते हैं, लेकिन बिना निगरानी के हिंसक सामग्री, अपमानजनक भाषा और आक्रामक व्यवहार के लगातार संपर्क में रहना चिंता का विषय हो सकता है। यदि कोई बच्चा गेम में बार-बार हिंसा को समस्या सुलझाने का तरीका देखता है और फिर वास्तविक जीवन में किसी विवाद के दौरान उसी तरह प्रतिक्रिया करता है, तो अभिभावकों और शिक्षकों को उसके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन केवल गेम पर प्रतिबंध लगा देना पर्याप्त नहीं है। बच्चे को यह समझाना भी जरूरी है कि डिजिटल दुनिया में दिखाई देने वाली हिंसा वास्तविक जीवन में स्वीकार्य नहीं है। उम्र के अनुरूप सामग्री, स्क्रीन टाइम की सीमाएं, ऑनलाइन मित्रों और चैट की निगरानी तथा खुले संवाद से जोखिम कम किया जा सकता है। इस जिम्मेदारी का पहला केंद्र परिवार है। माता-पिता बच्चों के लिए केवल नियम बनाने वाले नहीं, बल्कि उनके व्यवहार के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण भी हैं।

घर में गाली-गलौज, अपमान, मारपीट या हर समस्या का समाधान गुस्से से करने का तरीका बच्चों पर असर डाल सकता है। बच्चे को सुनना, उसकी भावनाओं को पहचानना, गलती पर शांतिपूर्वक समझाना और हिंसा के बजाय संवाद का रास्ता दिखाना जरूरी है। यदि बच्चा लगातार चिड़चिड़ा, भयभीत, अलग-थलग या आक्रामक हो रहा है, तो उसे दंडित करने से पहले कारण समझने और आवश्यकता पड़ने पर परामर्श लेने की जरूरत है। स्कूलों और समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में बुलिंग-विरोधी स्पष्ट नीति, संवेदनशील शिक्षक, भरोसेमंद शिकायत व्यवस्था और काउंसलिंग की सुविधा होनी चाहिए। पड़ोस, खेल समूह, मीडिया संस्थान और डिजिटल प्लेटफॉर्म बच्चों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा दें। किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा की घटना को बच्चों की आपसी बात कहकर टालना गलत है। बच्चे को सुरक्षित तरीके से बोलने का अवसर देना और उसकी शिकायत को गंभीरता से लेना समाज का दायित्व है।

शिशु आसन

करने से मिलते हैं कई फायदे



आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, थकान और घंटों बैठकर काम करने की वजह से शरीर में अकड़न महसूस होना आम बात है। ऐसे में योग की कुछ आसान मुद्राएं शरीर को आराम देने और मन को शांत करने में मदद कर सकती हैं। शिशु आसन, जिसे अंग्रेजी में चाइल्ड्स पोज और योग की कई परंपराओं में बालासन भी कहा जाता है, एक सरल विश्राम मुद्रा है। इस आसन में शरीर को आगे की ओर झुकाकर माथे को जमीन या किसी सहारे पर रखा जाता है। यह मुद्रा खासतौर पर योग अभ्यास के बीच आराम करने और सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोगी मानी जाती है। नियमित और सही तरीके से अभ्यास करने पर यह पीठ, कूल्हों और जांघों की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव देने के साथ तनाव कम महसूस करने में मदद कर सकती है। हालांकि, हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है, इसलिए आसन करते समय शरीर पर दबाव डालने से बचना चाहिए।

थकान के बाद विश्राम

शिशु आसन को योग सत्र के बीच आराम करने के लिए अपनाया जाता है। कुछ देर आराम से बैठने और सांसों पर ध्यान देने से शरीर को सहज महसूस हो सकता है। वहींयदि आपके कूल्हे एड़ियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप अपनी एड़ियों और हिप्स के बीच एक तकिया या मुड़ा हुआ कंबल रख सकते हैं। यदि माथा जमीन तक न पहुंचे, तो माथे के नीचे एक योग ब्लॉक या तकिया लगा लें। क्योंकि माथे को जमीन या योग मैट से छूने पर शरीर को स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव होता है, जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शांत होता है। घुटनों में तेज दर्द होने पर इस आसन को करने से बचें।

तनाव करे कम

शिशु आसन में आरामदायक स्थिति में रहकर धीमी और गहरी सांसें लेने से मन को शांत करने में मदद मिल सकती है। दिनभर की थकान के बाद यह मुद्रा विश्राम के लिए उपयोगी है।

कंधों को आराम



यदि हाथों को शरीर के आगे फैलाया जाए, तो कंधों और ऊपरी पीठ में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है। असुविधा होने पर हाथों को शरीर के पास भी रखा जा सकता है। वहीं इस आसन में आगे झुकने से पीठ की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव आता है। लंबे समय तक बैठने के कारण होने वाली सामान्य अकड़न में इससे आराम मिल सकता है। इसके अलावा गरूणासन भी विशेष रूप से कंधों और ऊपरी पीठ में गहरा खिंचाव लाता है। यह कंधों के भारीपन और वहां जमा मानसिक या शारीरिक तनाव को तुरंत दूर करने में सहायक है। वहीं गोमुखासन के अभ्यास से भी कंधे के कैप्सूल और छाती की मांसपेशियां खुलती हैं। यह ट्राइसेप्स और कंधों की जकड़न को हटाकर लचीलापन बढ़ाता है। स्कंध संचालन में अपनी उंगलियों को कंधों पर रखकर कोहनियों को गोलाकार घुमाने से कंधों के जोड़ों में सिनोवियल फ्लूइड सक्रिय होता है। इससे रक्त संचार तेज होता है।

कूल्हों और जांघों में लचीलापन

शिशु आसन कूल्हों और जांघों के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए एक बेहद आसान और असरदार योगासन है। यह शरीर को आराम देने के साथ-साथ निचले हिस्से की जकड़न को दूर करता है। योग मैट पर वज्रासन में बैठ जाएं। अपने दोनों पैर के अंगूठों को आपस में मिलाएं और घुटनों को बाहर की तरफ फैलाएं। गहरी सांस छोड़ते हुए अपने धड़ को आगे की ओर झुकाएं। अपनी छाती को जांघों के बीच लाने का प्रयास करें। अपने दोनों हाथों को सीधे आगे की ओर फैलाएं, हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। अपने माथे को आराम से जमीन से छुएं। इस मुद्रा में गहरी सांस लेते रहें और 30 सेकंड से 2 मिनट तक बने रहें। कूल्हों और जांघों पर आ रहे खिंचाव को महसूस करें। यह आसन आंतरिक जांघों और कूल्हों के जोड़ों को धीरे-धीरे खोलता है।

शरीर की जागरूकता बढ़ाए



बालासन वास्तव में मन और शरीर के जुड़ाव को गहरा कर शारीरिक जागरूकता को बढ़ाने में बेहद मददगार है। जब आप इस कोमल मुद्रा में झुकते हैं, तो यह आपके ध्यान को बाहरी दुनिया से हटाकर पूरी तरह से आंतरिक संवेदनाओं पर केंद्रित करता है। इस मुद्रा में पेट जांघों से दबा होता है, जिससे आप अपनी पीठ और पसलियों के पिछले हिस्से में सांस के विस्तार को गहराई से महसूस कर पाते हैं।

हंसना मना है

एक महिला पेट्रोल पंप पर पहली बार स्कूटी चला कर गई... महिला - भईया, पेट्रोल कितने रुपये लीटर है... कर्मी- मैडम 80 रुपये लीटर... महिला - ठीक से लगा लो भईया, बगल वाला तो 70 रुपये लीटर ही दे रहा है। कर्मी - (गुस्से में) अरे मैडम जी, बगल में डीजल की मशीन है...

बाजार में पप्पू को एक बेहद खूबसूरत महिला दिखी... पप्पू खड़ा होकर उसे देखता ही रह गया... तभी वो उसके पास आई और बोली - भाई साहब, दिख तो मैं आंख से भी जाऊंगी, मुंह तो बंद कर लो...

एक महिला ने एंबुलेंस बुलाने के लिए कॉल किया... ऑपरेटर - आपको क्या समस्या है? महिला - मेरे पैर की ऊंगली कॉफी टेबल से टकरा गई... ऑपरेटर (हंसते हुए) - तो इसके लिए आप एंबुलेंस बुलाना चाहती हैं? महिला - नहीं, एंबुलेंस तो मेरे पति के लिए है, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था...

चेन स्नैचिंग वाले महिला के गले से हार खींच कर ले गए...अगले दिन महिला बहुत ज्यादा दुखी हुई... हार के लिए नहीं, अखबार वालों ने छाप दिया- वृद्ध महिला के गले से हार छीन भागे चेन स्नैचर...

कहानी | कबूतर का घोंसला

एक बार गौतम बुद्ध शाम के समय कुटिया के बाहर शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी वहां एक कबूतर का जोड़ा उड़ता हुआ आ गया। उन्हें देख कर महात्मा बुद्ध को एक कहानी याद आई और उन्होंने शिष्यों को कहानी सुनाना शुरू किया। एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। कुछ समय बाद कबूतरी ने उसी पेड़ की टहनी पर तीन अंडे दिए। एक दिन कबूतर और कबूतरी खाना ढूंढते हुए कुछ दूर निकल गये। तभी कहीं से एक लोमड़ी आ गयी। वह भी भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ी। जहां उसे कबूतर के अंडे मिल गये और वो अंडों को खा गयी। जब कबूतर का जोड़ा वापस आया तो अंडे न पा कर बहुत परेशान हो गया। दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। उनका मन टूट सा गया। तभी कबूतर ने निश्चय किया कि अब वह घोंसला बनाएंगा। ताकि फिर कभी उसके अंडे कोई न खा जाए। कबूतर ने अपने निर्णय अनुसार तिनके इकट्ठे करके घोंसला बनाना शुरू किया। पर उसे एहसास हुआ कि उसे तो घोंसला बनाना आता ही नहीं है। तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया। सभी पक्षी उसकी मदद के लिए आ गये आर उन्होंने कबूतर के लिए घोंसला बनाना शुरू किया। पक्षियों ने अभी कबूतर को सिखाना शुरू ही किया था कि कबूतर ने बोला कि अब वो घोंसला बना लेगा। उसने सब सीख लिया है। सभी पक्षी यह सुन कर वापस चले गए। अब कबूतर ने घोंसला बनाना शुरू किया। उसने एक तिनका इधर रखा एक तिनका उधर। उसे समझ आया कि वह अभी भी कुछ नहीं सीखा है। उसने फिर से पक्षियों को बुलाया। पक्षियों ने आ कर फिर घोंसला बनाना शुरू किया। अभी आधा घोंसला बना ही था कि कबूतर जोर से चिल्लाया, तुम सब छोड़ दो अब मैं समझ गया हूं यह कैसे बनेगा। इस बार पक्षियों को बहुत गुस्सा आया। सारे पक्षी तिनके वहीं छोड़ कर चले गये। कबूतर ने फिर कोशिश की पर उससे घोंसला नहीं बना। कबूतर ने तीसरी बार पक्षियों को बुलाया, लेकिन इस बार एक भी पक्षी मदद के लिए नहीं आया और आज तक कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आया।

7 अंतर खोजें



जानिए कैसा रहेगा कल का दिन



पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष आपके निर्णय और काम करने का तरीका कार्यक्षेत्र में प्रभाव डाल सकते हैं। नए व्यावसायिक समझौतों पर विचार कर सकते हैं। आर्थिक लाभ की संभावनाओं का आकलन करें।

वृषभ दफ्तर में शांतिपूर्वक काम निपटाएं और अनावश्यक बातचीत से बचें। विदेश से जुड़े व्यापार या ऑनलाइन बिजनेस के अवसरों का आकलन करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन उच्च अधिकारियों की मदद से करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नए व्यावसायिक संपर्कों से व्यापार का विस्तार करने की योजना बना सकते हैं।

कर्क करियर में नए प्रोजेक्ट मिलने के अवसर तलाश सकते हैं। व्यापारिक सौदों में शर्तों और दस्तावेजों की जांच करें। घर के बड़ों का स्नेह और मार्गदर्शन मिल सकता है।

सिंह कठिन कामों को धैर्य और योजना के साथ पूरा करने का प्रयास करें। कारोबारी यात्राओं में नए संपर्क बन सकते हैं। मन प्रसन्न रखने के लिए पर्याप्त आराम करें।

कन्या अपनी योजनाओं और जरूरी जानकारियों को साझा करते समय विवेक से काम लें। व्यापार में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें खानपान में लापरवाही न करें।

तुला साझेदारी और नए प्रस्तावों पर विचार करने का अवसर मिल सकता है। व्यापार बढ़ाने के विकल्प तलाशें। धन लाभ के अवसरों का आकलन करके बचत पर ध्यान दें।

वृश्चिक मेहनत और लगन से कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करें। प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी रणनीति पर ध्यान दें। परिजनों का समर्थन मिल सकता है।

धनु आपकी रचनात्मकता की सराहना हो सकती है और नए अवसर मिल सकते हैं। नए निवेश से पहले जोखिम और संभावित लाभ समझें।

मकर कार्यस्थल पर शांति बनाए रखें और अनावश्यक बहस से बचें। जमीन, प्रॉपर्टी या ऑटोमोबाइल से जुड़े कारोबार में दस्तावेज जांचकर आगे बढ़ें। संतुलित भोजन लें।

कुम्भ अपने काम की गति और गुणवत्ता बनाए रखें। छोटे-छोटे लाभ को व्यवस्थित ढंग से बचत में बदलने का प्रयास करें। भाई-बहनों से सहयोग और स्नेह मिल सकता है।

मीन आपके विचारों को कार्यस्थल पर महत्व मिल सकता है। पुराने बकाए वसूलने के लिए लोगों से संपर्क करें। परिवार में खुशनुमा वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें।

कैकेयी जैसा किरदार निभाने का मौका कम लोगों को मिलता है : लारा दत्ता



फिल्म रामायण में लारा दत्ता रणबीर की सौतेली मां का रोल निभा रही हैं। खास बात यह है कि रणबीर उनसे महज चार साल छोटे हैं। फिल्म में लारा दत्ता 42 साल के अभिनेता आदिनाथ एम कोठारे की मां का किरदार भी निभा रही हैं। आदिनाथ फिल्म में कैकेयी के बेटे भरत की भूमिका में नजर आएंगे। लारा ने बताया कि उन्हें इन किरदारों को निभाने में उम्र के अंतर को लेकर कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अब हम इन सब बातों से आगे निकल चुके हैं। आज कलाकारों में ऐसी पुरानी सोच नहीं रह गई है कि मैं एक महिला कलाकार हूं, तो फलां किरदार कैसे निभाऊंगी? आज आप सिर्फ किरदार को जीते हैं। मेरे मन में इस तरह का जरा भी ख्याल नहीं आया। लारा ने आगे कहा, और जब आप पूरी कहानी को बड़े नजरिए से देखते हैं, तो दशरथ की तीन रानियां थीं। उनकी उम्र अलग-अलग थीं। कैकेयी का किरदार निभाने के लिए सबसे पहले नितेश सर और मैंने बैठकर उनके किरदार का पूरा इतिहास समझा। उन बातों पर भी चर्चा की, जो आपको फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे उन्होंने वे दो वरदान क्यों मांगे, उन्हें ये वरदान कब और कैसे देने का वादा किया गया था, वह कौन थीं और कहां से आई थीं। लारा ने यह भी कहा कि कैकेयी जैसा किरदार निभाने का मौका किसी कलाकार को बहुत कम मिलता है। इसलिए ऐसे मौके को दोनों हाथों से थाम लेना चाहिए।

दीपिका पादुकोण के आठ घंटे की शिफ्ट डिमांड के सपोर्ट में उतरीं आलिया भट्ट

साल 2025 में दीपिका पादुकोण का आठ घंटे की शिफ्ट डिमांड का मुद्दा काफी चर्चा में रहा था। कथित तौर पर ऐसी मांग को लेकर दीपिका को प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से बाहर होना पड़ा था। इसके बाद इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई थी। किसी ने दीपिका की मांग से असहमति जताई तो किसी ने दीपिका का सपोर्ट किया था। अब इस मुद्दे पर आलिया भट्ट ने भी अपनी बात रखी है और उन्होंने दीपिका की मांग का समर्थन किया है। आलिया भट्ट ने साफ किया है कि इस चीज में स्टार्स के सामने मनमानी नहीं होनी चाहिए। हाल ही में आलिया भट्ट ने टाइम को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने अपने फिल्ममेकर्स का जिक्र किया। उन्होंने खुद को लकी माना कि उनके साथ काम करने वाले प्रोड्यूसर्स ने उनकी जरूरतों को समझा और उनका ध्यान रखा। आलिया ने न सिर्फ एक्टर्स बल्कि क्रू मेंबर्स आदि के काम के घंटों को सीमित करने और उन पर दोबारा विचार करने के लिए भी कहा। बता दें कि कई क्रू मेंबर्स को दिन में 15 से 18 घंटे तक भी काम करना प?ता है। प्रोड्यूसर्स ने मेरी काफी मदद की। हालांकि इन चीजों पर दोबारा विचार हो। ये मनमाना नहीं होना चाहिए। आलिया ने आगे कहा कि जब काम के घंटे ठीक-ठाक हो तब काम और बेहतर तरीके से होता है। इन चीजों को लेकर लोगों को अपनी बाउंड्रीज तय करते वक्त अपनी नौकरी खोने का डर नहीं होना चाहिए। आलिया भट्ट ने आगे बातचीत में सेट पर महिलाओं के लिए बुनियादी चीजों की जरूरत पर भी जोर दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि सेट पर साफ-सुथरे टॉयलेट्स और बेहतरीन बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए।

आलिया भट्ट पिछली बार फिल्म अल्फा में नजर आई थीं जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अब एक्ट्रेस फिल्म लव एंड वॉर में नजर आने वाली हैं। इसमें उनके साथ उनके पति रणबीर कपूर और विकी कौशल भी लीड रोल में हैं। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये मूवी 21 जनवरी 2027 को थिएटर्स में रिलीज होगी।



मेरा और मिश्किन का रिश्ता काफी गहरा है : कीर्ति सुरेश



कीर्ति सुरेश अपनी अपकमिंग फिल्म सत्यवान सावित्री को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कीर्ति सुरेश और फिल्ममेकर मिश्किन का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में फिल्ममेकर और एक्ट्रेस एक साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मिश्किन अचानक कीर्ति सुरेश की जांघ पर हाथ रख देते हैं। वीडियो वायरल हुआ, तो लोगों ने इसे लेकर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। अब एक्ट्रेस ने पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। वायरल क्लिप में मिश्किन इवेंट के दौरान कीर्ति के पास बैठे दिखाई देते हैं। बातचीत के दौरान एक समय पर वो अपना हाथ कीर्ति की जांघ पर रख देते हैं। यह पल लोगों का ध्यान खींच गया और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्ममेकर के इस इशारे पर सवाल उठाए। कई यूजर्स को लगा कि कीर्ति इस बातचीत के दौरान असहज दिख रही थीं। कई लोग एक्ट्रेस की बॉडी लैंग्वेज पर चिंता जता रहे हैं। विवाद बढ़ने पर कीर्ति ने इस पर चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी बात कही। पहले, मेरे चेहरे पर असहजता कहां दिखी? क्या आपने उसकी या मेरी बात नहीं सुनी कि हमारा रिश्ता पिता-बेटी जैसा है? दूसरी, भले ही मैं असहज थी, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि हम फिल्मों में टच करते हैं। इसलिए पब्लिक में भी मुझे वैसा ही सहना चाहिए? आपको कुछ बातें ठीक करने की जरूरत है, भाई।

कीर्ति सुरेश ने अपना बयान देकर साफ कर दिया कि फिल्ममेकर मिश्किन और उनका रिश्ता काफी गहरा है। ना तो उन्होंने उन्हें गलत तरीके से टच किया और ना ही उन्हें मिश्किन के टच से परेशानी हुई। फिल्म की बात करें, तो प्रवीण एस। विजय द्वारा निर्देशित सत्यवान सावित्री एक आगामी कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें कीर्ति सुरेश एक वकील की भूमिका में हैं। मिश्किन एक सीनियर एडवोकेट का किरदार निभाते हैं, जो बाद में अदालत में उनका सामना करता है। यह फिल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

जल्द ही ओटीटी पर डेब्यू करेंगी तब्बू

तब्बू, YRF एंटरटेनमेंट की नेटफ्लिक्स सीरीज टनल मेन में नजर आने वाली हैं। यह उनका पहला हिंदी ओरिजिनल स्ट्रीमिंग शो होगा। टनल मेन एक काल्पनिक ड्रामा है, जो 2023 में उत्तराखंड टनल रेस्क्यू (सुरंग बचाव अभियान) की भावना से प्रेरित है। नवंबर 2023 में, पूरा देश सांस थामे उस लंबे और कठिन बचाव अभियान को देख रहा था, जिसमें उत्तराखंड की एक ढही हुई सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। टनल मेन उसी पल की भावना को दिखाती है। इसमें शामिल लोगों का जज्बा, टीम वर्क और वह उम्मीद, जिसने उन्हें हार नहीं मानने दी। (तब्बू का करियर तीन दशकों से भी ज्यादा लंबा है। वह मेनस्ट्रीम और स्वतंत्र (इंडिपेंडेंट) सिनेमा के साथ-साथ हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। माचिस और चांदनी बार में उनके किरदारों के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिले, जबकि मकबूल, हैदर और अंधाधुन में उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखाई।



उनके अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में एंग ली की लाइफ ऑफ पाई, मीरा नायर की द नेमसेक (जिसमें उन्होंने आशिमा गांगुली का किरदार निभाया था) और ड्यून- प्रोफेसी सीरीज शामिल हैं, जिसमें वह सिस्टर फ्रांसेस्का के रूप में नजर आईं। द रेलवे मेन के डायरेक्टर शिव रवैल, टनल मेन में शो-रनर के तौर पर वापसी कर रहे हैं। वे एक बार फिर मानवीय संवेदनाओं पर आधारित अपनी कहानी कहने की शैली को साहस की एक नई कहानी के जरिए पेश करेंगे। टनल मेन सौगत मुखर्जी का YRF एंटरटेनमेंट में हेड ऑफ कंटेंट अक्षय विधानी) के तौर पर जुड़ने के बाद पहला प्रोजेक्ट है।

सैफ अली खान को मिली धमकी

बॉलीवुड सितारों को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सलमान खान से लेकर दूसरे फिल्मी सितारों तक, कई कलाकार पहले ही धमकियों का सामना कर चुके हैं। अब इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान का नाम भी जुड़ गया है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सैफ को धमकी मिली है और इस मामले में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के वांटेड आरोपी जीशान अख्तर का नाम सामने आ रहा है।



बताया जा रहा है कि जीशान अख्तर ने सैफ अली खान को धमकी दी है। हालांकि, पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि धमकी वास्तव में जीशान अख्तर ने ही दी है या फिर उसके नाम का इस्तेमाल कर कोई दूसरा शख्स डर फैलाने की कोशिश कर रहा है।

इस मामले में जीशान अख्तर का नाम सामने आने के बाद मुंबई पुलिस की जांच और अहम हो गई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड जीशान अख्तर को लेकर पुलिस पहले से ही सतर्क है। अब सैफ अली खान को मिली धमकी में उसका नाम सामने आने से बॉलीवुड और पुलिस महकमे में हलचल है।

हालांकि, अभी तक धमकी देने वाले की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही है।

राजस्थान में प्रसूता की मौत मामले में सियासी बवाल

» कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

» प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व भाजपा अध्यक्ष में वार-पलटवार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान में प्रसूता की मौत मामले में सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस ने भाजपा की भजन सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर एम्स की रिपोर्ट दबाने और दोषी डॉक्टरों को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनके आरोपों पर पलटवार किया है। ताजा मामले में बारां जिले की 31 वर्षीय प्रसूता फुला बाई को गंभीर हालत में 11 नवंबर को कोटा रेफर किया गया था। यहां पहले एमबीएस अस्पताल और फिर न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका उपचार किया गया।

करीब दो दिन तक सघन उपचार के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इससे पहले बारां की ही पुष्पा बैरवा की भी कोटा में मौत हो गई थी। पुष्पा को झालावाड़ से रेफर किया गया था। कोटा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में उपचार के दौरान उसे अत्यधिक ब्लीडिंग हुई। इसके बाद उसकी किडनी, लीवर और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। मई 2026 में सीजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की मौत के मामलों की जांच के लिए दिल्ली एम्स की विशेषज्ञ टीम बुलाई गई थी। जांच रिपोर्ट में ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही, संक्रमण नियंत्रण में खामियां और निर्धारित मेडिकल प्रोटोकॉल की अनदेखी जैसे गंभीर तथ्य सामने आने की बात कही गई थी। इसके बावजूद राज्य सरकार की आंतरिक कमेटियों ने निलंबित तीन डॉक्टरों को क्लीन चिट देकर बहाल कर दिया। लगातार सामने आ रही मौतों के बाद चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं।



एम्स की रिपोर्ट दबाकर डॉक्टरों को बचा रही सरकार : डोटासरा

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रसूताओं की मौत के मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के प्रतिष्ठित संस्थान एम्स की जांच रिपोर्ट में चिकित्सकीय लापरवाही सामने आने के बावजूद सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। डोटासरा का कहना है कि रिपोर्ट छिपाकर दोषी डॉक्टरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि लगातार प्रसूताओं की मौत के बावजूद सरकार जिम्मेदारी तय करने के बजाय मामले से बचने का प्रयास कर रही है।

मदन राठौड़ बोले- प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाएं पहले से बेहतर



भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से जब प्रसूताओं की मौत और मदन दिलावर की टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने दिलावर के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि, डोटासरा के आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया। राठौड़ ने कहा कि गोविंद सिंह गलत जानकारी दे रहे हैं। उनके मुताबिक प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है और पहले से बेहतर बनाया गया है।

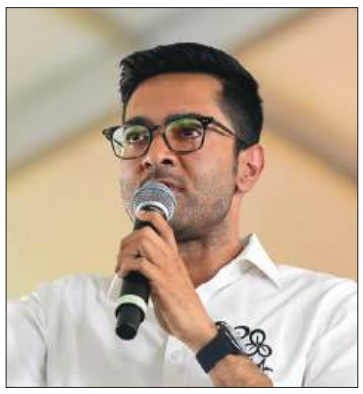
दिलावर ने डोटासरा के मानसिक संतुलन पर की टिप्पणी

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दौरे पर कोटा पहुंचे थे। प्रसूताओं की मौत और एम्स की रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा से जुड़े विषयों पर चिकित्सा मंत्री ही जानकारी दे सकते हैं। उनके पास इस मामले से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, डोटासरा के आरोपों पर पलटवार करते हुए दिलावर ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने डोटासरा को अपना अच्छा मित्र बताते हुए कहा कि आजकल उनकी स्थिति ठीक नहीं है और उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है।

न्याय को सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार नहीं बनाना चाहिए

» निजी सहायक सुमित रॉय की याचिका खारिज होने पर बिफरे अभिषेक बनर्जी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क



कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को कानूनी राहत के कथित चयनात्मक इस्तेमाल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि न्याय सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार नहीं बनना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उनके निजी सहायक सुमित रॉय की उस याचिका को खारिज किए जाने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने चार आपराधिक मामलों में अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। इन मामलों में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, न्याय सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार और विपक्ष का निरंतर संघर्ष नहीं बन सकता। ऐसा लगता है कि राहत केवल भाजपा नेताओं और उनके करीबी लोगों के लिए आरक्षित है, जबकि विपक्ष को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

टीएमसी नेता की यह प्रतिक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा चार मामलों में रॉय की अंतरिम सुरक्षा की मांग को खारिज करने के बाद आई है। रॉय फिलहाल सालबोनी में जमीन घोटाले के एक कथित मामले के सिलसिले में हिरासत में हैं। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने की। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में रिट कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए, खासकर तब जब पीड़ित व्यक्ति के पास कानूनी राहत के अन्य विकल्प मौजूद हों। रॉय ने चार मामलों में अंतरिम सुरक्षा पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिनमें उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया था। उनके वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक कारणों से कई मामले दर्ज किए गए हैं। वकील ने यह भी कहा कि रॉय को बाकी चार मामलों में सुरक्षा की जरूरत है, जबकि वह उस मामले में कानूनी उपाय अपना रहे हैं जिसमें वे अभी हिरासत में हैं। हालांकि, अदालत ने रॉय द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने नए मामलों और सख्त कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा देने से किया मना

सुनवाई के दौरान, रॉय ने अधिकारियों को उनके खिलाफ नए मामले दर्ज करने या मौजूदा मामलों में सख्त कार्रवाई करने से रोकने का आदेश भी मांगा। जस्टिस भट्टाचार्य ने इस अनुरोध को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आपराधिक मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, खासकर तब जब संबंधित व्यक्ति के पास अन्य कानूनी उपाय उपलब्ध हों। इस फैसले का मतलब यह है कि रॉय को उन चार मामलों में वह अंतरिम सुरक्षा नहीं मिली, जिसकी उन्होंने मांग की थी।

भारतीय बल्लेबाजों का दूसरे दिन दिखा दम

» यशस्वी-राहुल के अर्धशतक न्यूजीलैंड पहली पारी में 368 रन पर सिमटी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

वेलिंगटन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए। जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में एक विकेट पर 159 रन बनाए हैं और वह अभी 209 रन पीछे है। भारत को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अच्छी शुरुआत दिलाई और दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। स्टंप्स के समय केएल राहुल 52 और देवदत्त पडिक्कल 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत को एकमात्र झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। वह शतक से चूक गए। यशस्वी ने 89 गेंद पर 16 चौके की मदद से 85 रन की तेज पारी खेली।

यशस्वी ने टेस्ट करियर का 14वां अर्धशतक लगाया।

यशस्वी ने पहले विकेट के लिए राहुल के साथ 130 रन जोड़े। इसके बाद राहुल ने भी टेस्ट करियर का 22वां अर्धशतक पूरा किया। यशस्वी को मैट हेनरी ने विकेटकीपर ब्लंडेल के हाथों कैच कराया। राहुल और यशस्वी ने कुछ मुश्किल क्षणों का सामना किया। भारत ने अपना पहला रन पांचवें ओवर में बनाया जब जायसवाल का कवर ड्राइव शॉट वाइड थर्ड स्लिप के ऊपर से निकलकर चौके के लिए चला गया। इससे पहले, दूसरे दिन मेजबान टीम की पहली पारी 368 रन पर समाप्त हो गई थी। न्यूजीलैंड ने पांच विकेट पर 243 रन से आगे खेलना शुरू किया। दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने 125 रन जोड़े और बाकी के पांच विकेट गंवा किए। हेनरी निकोल्स 175 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 118 रन की शानदार पारी खेली। एक वक्त न्यूजीलैंड ने 70 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद इन दोनों ने छठे विकेट के लिए 216 रन की साझेदारी कर न्यूजीलैंड को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला।



भाजपा समर्थकों ने पत्थर और अंडे फेंके : महुआ मोइत्रा

» टीएमसी सांसद के काफिले पर हमला, मचा बवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कालीगंज में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों के एक समूह ने उनकी कार और काफिले पर पत्थर तथा अंडे फेंके। उन्होंने आरोप लगाया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य पुलिस उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही। कृष्णानगर की सांसद ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर सिलसिलेवार किए कई पोस्ट में दावा किया कि 80-90 भाजपा समर्थक गोबरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में उन पर हमला करने के लिए जमा हुए थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को इस जमावड़े की पहले से जानकारी थी। मोइत्रा ने पोस्ट किया, पश्चिम बंगाल पुलिस, पुलिस महानिदेशक और कृष्णानगर पुलिस का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के तहत मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। कालीगंज के गोबरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में भाजपा के 80-90 गुंडे मुझ पर हमला करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको इस बारे में सारी जानकारी है। उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थकों के साथ मिलीभगत करने और अदालत के आदेश पर की गई सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद उन्हें हमला करने देने का आरोप लगाया।

आम सूचना

आम सूचना मेरे पक्षकार सुधीर सक्सेना पपता स्व.श्री रमाशंकर लाल सक्सेना की ओर से सर्व साधारण को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया है कि मकान नंबर म.क्र .बी-2/320, सेक्टर ए, सीतापुर रोड योजना, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (पिन - 226024), जो कि स्व. श्री अशोक सक्सेना (पुत्र स्व. श्री रमाशंकर लाल सक्सेना) के पूर्ण स्वामित्व और आधिपत्य की अचल संपत्ति है जिसका स्वामित्व वर्तमान में विवादित है। उक्त संपत्ति के स्वामी स्व. अशोक सक्सेना थे जिनका निधन हो चुका है, उनकी पत्नी स्व. श्रीमती आशा सक्सेना एवं उनके इकलौते पुत्र स्व. अमित सक्सेना (अविवाहित) का भी स्वर्गवास हो चुका है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत स्व. अशोक सक्सेना का कोई भी प्रथम श्रेणी का वैधानिक उत्तराधिकारी वर्तमान में जीवित नहीं है जिस कारण उत्तराधिकार विधि अनुसार स्व. अशोक सक्सेना की उक्त संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके पैतृक पक्ष के जीवित सदस्य हैं। स्व. अशोक सक्सेना के जीवित सगे भाई क्रमश: सुधीर सक्सेना (निवासी-भोपाल), सुबोध सक्सेना एवं सुनील सक्सेना ही कानूनन उक्त संपत्ति के एकमात्र वैध उत्तराधिकारी और वारिसान हैं । वैध वारिसानों द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एवं प्रशासन पत्र प्राप्त करने हेतु विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है । वैध वारिसानों को विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उक्त संपत्ति को किसी अन्य व्यपक्त द्वारा स्वयं की संपत्ति बताकर उक्त संपपि को बेचने, अंतरित करने या किसी भी प्रकार का तृतीय पक्ष अपधकार सृजित करने का अवैध प्रयास किया जा रहा है या किया गया है । अत: इस लोक सूचना के माध्यम से सर्व साधारण व्यक्त, आम जनता, प्रॉपर्टी डीलरों, विकासकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों को सचेत एवं आगाह किया जाता है कि वे उक्त संपपि म.क्र .बी-2/320, सेक्टर-ए, अलींगज, लखनऊ के संबंध में उपरोक्त वैध उत्तराधिकाररयों के सिवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का क्र य-विक्र य, बयाना, लीज, बंधक या अन्य कोई भी संव्यवहार न करें । यदि कोई भी व्यपक्त या संस्था उक्त पववापित संपति के संबंध में किसी भी प्रकार का वित्तीय या व्यावसायिक लेन देन करता है या कर चुका है तो ऐसा कोई भी संव्यवहार अवैध, शून्य (वॉयड) और वैध उत्तराधिकारियों पर गैर-बाध्यकारी हो तथा उसके लिए वैध उत्तराधिकारी जिम्मदार नहीं होंगे। वैध वारिसान ऐसे किसी भी अवैध कृत्य के विरुद्ध दीवानी एवं आपराधिक कानूनी कार्यवाही करने के लिए पूर्णत: स्वतंत्र होंगे। यपि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है या उसने ऐसा कोई संव्यवहार ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से कर लिया है तो अवैध होंगे एवं ऐसा कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां/शिकायत मय दस्तावेज अधिवक्ता आकाश आंबेडकर के कार्यालय में आज दिनांक से 30 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से प्रेषित/प्रस्तुत कर सकते हैं।

आकाश अम्बेडकर जी एडवोकेट एंड एसोसिएट

20-11-2026

correspondent At - H-187 Ishaan Grand Estate. Hoshangabaad Road. Misrod. Bhopal MP-462047

Email-ambedkar.adv@gmail.com Mob +919407190700 +919752400928

ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की बैठक के बाद भारत में मचा सियासी बवाल

» नेता प्रतिपक्ष की समझौता करने वाले पीएम वाली पोस्ट पर भड़की भाजपा

» राहुल गांधी बोले- कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस टेबल पर बैठे होते

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क



नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की एक साथ बैठक के लेकर भारत में सियासी बवाल मचा गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस व भाजपा में वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोला है।

राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो भारत का प्रधानमंत्री भी इस ग्लोबल पावर सेंट्रल टेबल पर मौजूद होता। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा अगर कांग्रेस सत्ता में होती, तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस टेबल पर बैठे होते एक कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री कभी इस टेबल पर नहीं बैठ सकता। इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस ने भारत में भाजपा की राजनीतिक अवधारणा को काफी हद तक कमजोर कर दिया है. उन्होंने कहा %हमने भारत में भाजपा की राजनीतिक सोच को लगभग ध्वस्त कर दिया है. इसका असर अगले आठ महीनों में दिखाई देगा.% राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भाजपा का आंतरिक ढांचा कमजोर हो चुका है और केंद्र सरकार के कुछ मंत्री भी विपक्ष के संपर्क में हैं तथा जानकारियां साझा कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कांग्रेस पर समझौता करने का आरोप पुख्ता करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पाकिस्तान के युद्धबंदियों को रिहा किए जाने और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान आए शर्म-अल-शेख बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते के दौरान समझौता कर लिया था। उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया।



नकारात्मक नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे राहुल : आरपी सिंह



बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर भारत के बारे में नकारात्मक नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सच तो यह है कि आज विश्व व्यवस्था में भारत का कद ऊंचा है। प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिनके दुनिया भर के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। इससे पहले भारत की विदेश नीति पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने भारत को वैश्विक भू-राजनीति में एक साइड प्लेयर बताकर बीजेपी के साथ राजनीतिक टकराव खड़ा कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करने की अपनी क्षमता खो दी है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान जैसी बड़ी ताकतों के साथ जुड़ रहा है।

भारत को बदनाम करने के लिए मिले पैसे : तुहिन सिन्हा

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने वाली पोस्ट की। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। इस पोस्ट पर बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई और बदले में पिछली कांग्रेस सरकार पर भारत के हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा नेआरोप लगाया कि और सत्ता से बाहर रहने पर कांग्रेस पार्टी का यह हाल होता है... 7 अगस्त 2008, बीजिंग। कांग्रेस और सीसीपी (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) के बीच एक गुप्त समझौता हुआ, जिसके बाद चीन की घुसपैठ कई गुना बढ़ गई... और इसी घुसपैठ के साथ-साथ राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा भी मिलने लगा।उन्होंने आगे कहा कि और पैसे, शर्म अल-शेख की शर्मनाक घटना को कौन भूल सकता है? 2011 में शर्म अल-शेख में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री सैयद यूसुफ रजा गिलानी। क्या भारत ने कभी 2004-14 की यूपीए सरकार से ज्यादा समझौतावादी सरकार देखी हैबीजेपी नेता ने आरोप लगाया, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को भारत को बदनाम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं।



सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को लगा बड़ा झटका

» कर्नाटक से 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी मांगने वाली याचिकाएं खारिज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों- तमिलनाडु और कर्नाटक- के बीच दशकों से चले आ रहे कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की उन दो प्रमुख याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) अतिरिक्त पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।



सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और फैसला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए न केवल इन दोनों मुख्य याचिकाओं को खारिज किया, बल्कि तमिलनाडु सरकार द्वारा रिकॉर्ड पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेज लाने के लिए दायर की गई एक तीसरी अर्जी को भी नामंजूर कर दिया। इससे पहले, 12 अक्टूबर को हुई विस्तृत सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के इस रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वह विशेषज्ञ समितियों के तकनीकी आकलन में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि 8 अक्टूबर को, कावेरी जल विनियमन समिति ने कर्नाटक को पानी की कमी पूरी करने का निर्देश देने के बजाय, 9 अक्टूबर से पानी के बहाव को 4,000 क्यूसेक से घटाकर 3,000 क्यूसेक कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने मांग की कि कर्नाटक सरकार को 24 सितंबर के(कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण) के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, 24 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पानी की आपूर्ति में हुई 0.94 टीएमसी की कमी को पूरा किया जाए, और 8 अक्टूबर को सीएमडब्ल्यू की बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) के अनुसार आगे पानी का बहाव सुनिश्चित किया जाए। 24 सितंबर को, कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु की उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें उसने कावेरी नदी के अपने हिस्से का पानी छोड़ने की मांग की थी। तमिलनाडु का आरोप था कि उसे मिलने वाले पानी में कमी की गई है।

पीएम मोदी को हारने का डर, इसलिए वोट छीन रहे: रेवंत रेड्डी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास है, राजा लोग तय नहीं करेगा की सरकार कौन चलाएगा, हमें इसके लिए वोट का अधिकार दिया गया. वो तय करेंगे कि सरकार किसकी होगी।

रेड्डी ने कहा, 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने। पहले ईडी-सीबीआई का इस्तेमाल किया, इसके बाद ये लोग भाषा-जाति के नाम पर बांटने लग, लोगों ने सुनना छोड़ दिया, डरना बंद कर दिए, जंतर-मंतर पर आंदोलन हुआ, मोदी जी को पता लग गया कि पीड़ित, दलित, गरीब, आदिवासी महिलाओं को वोट का हक मिला तो वो हारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने दो तरह की जनता को तैयार किया, अमीर को वोट देने का अधिकार दिया, गरीब को हटा दिया। इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते है, गरीब का हक छीन रहे हैं, कोई मदद कर सकता है, इस देश का नागरिक हो, ये जरूरी नहीं है, आरएसएस और पीएम मोदी यूएस जा रहे हैं, आप हर देश में जा सकते हैं।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बढ़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट का अलग सुनवाई से इनकार

» कहा- पांच जजों की बेंच करेगी विचार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में 2023 के उस कानून पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (सीजेआई) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है।

दरअसल, इस कानून को चुनौती देने वाले मामले में दो जजों की बेंच ने अलग-अलग राय दी थी। अब इस बंटे हुए फैसले को वापस लेने और मामले पर दोबारा विचार करने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की एक पीठ ने कहा कि रीकॉल (वापसी) आवेदन, और साथ ही रेफरेंस आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर, पांच न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ की ओर से विचार किया जा सकता है, जिसे पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठित किया गया है। सीजेआई ने यह भी कहा कि पांच जजों की बेंच रिकॉल एप्लीकेशन (फैसले को वापस लेने की अर्जी) पर तब भी विचार कर सकती है, जब उस बेंच के जजों में से कोई एक रिटायर हो जाए, जिसने वह स्प्लिट वर्डिक्ट (बंटा हुआ फैसला) दिया था। भूषण ने कहा कि इस रिकॉल एप्लीकेशन को उसी मूल बेंच के सामने रखा जाना चाहिए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, जिन्होंने 23 सितंबर को यह स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था।

सीजेआई ने दिया सुझाव

जब सीजेआई ने सुझाव दिया कि रेफरेंस बेंच (मामले को आगे भेजने वाली बेंच) इस अर्जी पर विचार कर सकती है, तो भूषण ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप के कारण खुद उस रेफरेंस ऑर्डरको ही वापस ले लिया गया था। हालांकि, सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे को पांच जजों की उस संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है, जिसे 2023 के कानून को दी गई संवैधानिक चुनौती पर अंतिम फैसला लेने के लिए गठित किया गया है।यह घटनाक्रम 23 सितंबर को जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा द्वारा दिए गए उस स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद सामने आया है, जिसमें यह तय होना था कि क्या 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच की जरूरत है या नहीं।





महाराष्ट्र कार्यालय:- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। **विधि सलाहकार**: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी **4** पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक **संजय शर्मा**
द्वारा **आस्था प्रिंटर्स**, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। **संपादक- संजय शर्मा**